स्वतंत्रता दिवस संबोधन-2025

मेरे प्रिय साथियो,

परंपरा अनुसार हम हर साल इस पावन अवसर पर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का स्मरणोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। यह ऐतिहासिक दिन उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि है जिनके सामूहिक प्रयासों से देश को आजादी मिली।

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं, मुख्यालय, संरक्षा अनुसंधान संस्थान-कलपक्कम, क्षेत्रीय नियामक केंद्रों, विभिन्न स्थलीय संरक्षा अधिकारियों (एसओटी) और प्रशिक्षुओं (ओजेटी), सहायक एवं सहयोगी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, कैंटीन कर्मचारियों और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एईआरबी के कामकाज से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

एक नागरिक के रूप में, 'अमृत काल' के रूप में मनाए जा रहे इस ऐतिहासिक युग का हिस्सा बनना हम सभी के लिए वास्तव में बहुत गर्व की बात है। सभी क्षेत्रों में समग्र और समावेशी विकास के लिए नीतियों को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है और सुधार किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में, सरकार ने विकासशील भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा अभियान की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है ताकि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके।

उपरोक्त के मद्देनजर और 1962 से अब तक परमाणु नीतियों में हुए विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को संज्ञान में लेते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट सत्र में घोषणा की थी कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ("एईए, 1962") के साथ-साथ परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 ("सीएलएनडीए, 2010") में संशोधन किया जाएगा ताकि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जो निजी क्षेत्रों को गैर-विद्युत अनुप्रयोगों में निरंतर भागीदारी के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदारी की अनुमति दे।

इस संबंध में, विधायी प्रक्रिया तीव्र गति से जारी है। लेकिन कानूनी ढाँचा तो एक छोटा सा हिस्सा है, जो सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करने की नींव मात्र रखता है। यदि अनुप्रवाह तंत्र इस चुनौती

का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो यह प्रयास बेकार साबित होगा। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में, नियामक संस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आम धारणा यह है कि नियमन विकास की गति को धीमा करने वाली बाधा और रुकावट है। एईआरबी को इस धारणा को झुठलाने की चुनौती स्वीकार करना है और अपने आचरण से यह प्रदर्शित करना है कि वह एक जीवंत नियामक है, जो उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति सजग रहता है और साथ ही श्रमिकों, जनता और पर्यावरण के संरक्षा हितों का भी पूरा ध्यान रखता है।

यह एक बहुत ही कठिन रास्ता है जिस पर एईआरबी को एक अच्छा संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। यह केवल आत्म-साक्षात्कार और आत्म-जागरूकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ आंतरिक विवेक ही व्यक्ति की जवाबदेही और जिम्मेदारी की कुंजी होगा। किसी भी बाहरी अनुनय या प्रशिक्षण से यह आत्मीयता की भावना विकसित नहीं हो सकती।

मेरी समझ से, हमारी सभी गतिविधियाँ www.h (अर्थात् क्यों, क्या, कब और कैसे) द्वारा संचालित होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय सभी कर्मचारियों के साथ "क्यों" पर चर्चा करने से "क्यों" की स्पष्ट समझ आती है, जिससे स्वाभाविक रूप से "स्वामित्व" (अर्थात, जवाबदेही के साथ ज़िम्मेदारी) के भाव का जनन होता है। और यह स्वामित्व, कर्मचारियों को "क्या करें", "कब करें" और "कैसे करें" के माध्यम से "क्यों" को वास्तविकता में बदलने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित निर्णयों को छोड़कर, अन्य सभी निर्णय प्रसंगों के आधार पर होते हैं। अतीत के निर्णय आज के संदर्भ में अनुचित या 'बेतुके' लग सकते हैं, लेकिन उस समय के संदर्भ में देखने पर, हम पाते हैं कि वही सर्वोत्तम थे।

तर्क बिंदु यह है कि जिसने हमें अतीत में सफलता दिलाई, ज़रूरी नहीं कि वह हमें वर्तमान परिस्थितियों में भी और सफलता दिलाए। आत्मनिरीक्षण और पूर्वव्यापी विश्लेषण हमारे पिछले तरीकों को फिर से मान्य करने एवं बदलाव की ज़रूरत को पहचानने के लिए ज़रूरी हैं। यह जरूरी नहीं कि विकास प्रक्रिया के संरचित तरीके त्वरित विकास के चरण के लिए भी सही हों।

इस पृष्ठभूमि के साथ, हमने समावेशी और सहभागी तरीके से आत्मनिरीक्षण और पूर्वव्यापी विश्लेषण के लिए 'मंथन सत्र' शुरू किए। सोच यह थी कि हम में से प्रत्येक सामूहिक रूप से निर्णय लेकर अपनाएं, जो कि एक अग्रणी संगठन की सच्ची पहचान बनते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको अपनाकर मैं इसका पोषण करता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का अपार समर्थन और दृढ़ विश्वास मिला है, उसके साथ हम संरक्षा नियमों में उच्चतम मानक स्थापित करके एक नए पथ के जनक बन सकेंगे।

'मंथन' के प्रमुख परिणामों, जिन्हें मैं आपके साथ ईमेल और नोट्स के माध्यम से बार-बार साझा करता रहा हूँ, पर ध्यान खींचने की बजाय मैं कुछ खास पहलुओं पर ज़ोर देना चाहूँगा, जो एईआरबी को एक आदर्श के रूप में उभरने में मदद करेंगे।

एईआरबी को उसकी नियामक शक्तियों के डर से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और सक्षम कार्यबल के लिए सम्मान मिलना चाहिए। हमें विनियमित संस्थानों को इस बात के प्रति संवेदनशील बनाकर प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए कि नियामक कार्रवाई उनकी बेहतरी के लिए है और संरक्षा उत्पादकता में सहायक होती है। चुनौती इतनी है कि ऐसी कार्रवाइयों से लाभ तो निश्चित मिलते हैं, लेकिन तत्काल या दृश्यमान नहीं होते। इसलिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि नियामक कार्रवाइयों में यदि श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण को न्यायसंगत तरीके से लगाया जाए, तो यह लाइसेंसधारियों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। संस्थान, नियामक को एक अलग-थलग इकाई के रूप में नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से के रूप में देख सकेंगे। लाइसेंसधारी और जनता का विश्वास और भरोसा जीतने के अलावा इससे अंततः अनुपालन-उन्मुख होने से निरंतर सुधार की ओर की मानसिकता विकसित करने में मदद मिलेगी।

अगला बिंदु जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा, वह यह है कि विनियम यथासंभव व्यावहारिक और पेशे या व्यवसाय की विशिष्टताओं के अनुरूप होने चाहिए। अन्यथा, ऐसे विनियम केवल कागज़ों पर ही रह जाएँगे और लागू नहीं हो सकेंगे। विनियमों में, भिन्नता/अपवादों को समायोजित करने के लिए लचीलापन भी होना चाहिए। इस संबंध में, विकिरण अनुप्रयोग क्षेत्र के लिए तैयार किए जा रहे अभ्यास-विशिष्ट दिशानिर्देशों के लिए हितधारक मतों को ध्यान में रखकर पहली बार समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। 'विनियमों और मार्गदर्शन के विकास और संशोधन हेतु कार्यनीतियाँ एवं कार्यनीतिक दिशानिर्देश' तथा 'विनियमों और मार्गदर्शन के विकास और संशोधन की प्रक्रिया' पर हाल ही में जारी किए गए आईएमएस दस्तावेज़ इस भावना को मूर्त रूप देते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इन दस्तावेज़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कथन के पीछे के "क्यों" को समझें।

एईआरबी को अग्रसक्रिय कदम उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को शामिल करने की सरकार की पहल से अवगत हो जाने से, एईआरबी को न केवल भविष्य में उनके नियमन के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि नए प्रवेशकों (आपूर्ति श्रृंखला संस्थाओं सहित) को अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताने में भी सक्षम होना चाहिए ताकि बाद में कोई बड़ी अप्रत्याशित स्थिति या गतिरोध पैदा न हो। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू परमाणु उद्योग में 'संरक्षा संस्कृति' का महत्व है। एईआरबी जल्द ही संभावित नए प्रवेशकों के लिए एक समर्पित संगोष्ठी आयोजित करके ऐसे उद्योगों से रूबरू होगा।

एईआरबी एक युवा संगठन है जिसके कर्मचारियों की औसत आयु 40 वर्ष से कम है। युवा पीढ़ी तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक कुशल है और सोशल मीडिया टूलों से अधिक परिचित है। हमें इस पर काम करना चाहिए कि युवाओं की अप्रयुक्त प्रतिभाओं का लाभ कैसे लिया जाए। मैं दृढ़ता से इस बात की वकालत करता हूँ कि हम सामान्य नौकरशाही मानदंडों से हटकर युवाओं को सूचना साझा करने के अधिक रास्ते दें। सीखना हमेशा दोतरफा होता है और एईआरबी में वरिष्ठों को कनिष्ठों से सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। वरिष्ठों की परिपक्वता और युवाओं के नवोन्मेषी विचारों से क्रांतिकारी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है। इस संबंध में, मुझे 'मंथन' के दौरान युवा स्वयंसेवकों द्वारा एआई के उपयोग में दिए गए नवोन्मेषी सुझावों का स्मरण आता है। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं। 'मंथन' का एक परिणाम, ज्ञान साझा करने और उभरते मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सजीव (ऑनलाइन) मंच प्रदान करना, जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

मेरी इच्छाओं की सूची अंतहीन हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक, आने वाले दिनों में इन विचारों के दूत के रूप में काम करेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ज़ाहिराना तौर पर बेशक ये उपाय अपने आप में कोई खास बदलाव ना ला पाएं, लेकिन संपूर्णता की दृष्टि से देखने पर इनके दूरगामी परिणाम अवश्य होंगे, जैसा कि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने कहा था, *"संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है"*।

एक बार पुन: आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ।

'जय हिंद'

Independence Day Address-2025

My dear colleagues,

As per the tradition, we assemble every year on this solemn occasion to commemorate the freedom from the British Rule. This historic day is a tribute to the countless freedom fighters and ordinary citizens whose collective efforts led to the nation's liberation.

On the accession of 79th Independence Day, I extend my wishes to all my colleagues of AERB located at Headquarters, Safety Research Institute-Kalpakkam, Regional Regulatory Centres, SOTs and On Job Trainees posted at various sites, auxiliary and support staff, security personnel, canteen staff and one and all who are directly or indirectly connected with functioning of AERB.

As a citizen, it is indeed a great pride for all us to be part of this history era, being celebrated as Amrit kaal. Policies are being redefined and reforms are being made for a wholesome and inclusive growth in all sectors. Long Term Goals have been set with self-reliance at its core. In the energy sector, the Government has announced an ambitious Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat with a target of reaching a nuclear power capacity of 100 GW by 2047 to contribute significantly in achieving the target of Net Zero emissions by 2070.

In view of the above and considering the various geo-political developments in nuclear policies that has taken place since 1962, Hon'ble Finance Minister in this year's Budget session had announced that amendment in Atomic Energy Act, 1962 ("AEA, 1962") along with the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 ("CLNDA, 2010") would be taken up to usher in a regime that allows participation of the private sector in nuclear energy generation alongside their ongoing participation in non-power applications.

In this regard, the legislative developments are taking place at a rapid pace. However, the legal framework is only the tip of the iceberg. It only lays the foundation for realization of Government's long term vision. This in itself would be a dead letter if the downstream machinery are not geared up to take up the challenge. In the entire ecosystem, the regulatory body has a very crucial role to play. The general notion is that regulations are impediments and roadblocks which slow down the pace of development. AERB must take up the challenge to break this perception and demonstrate by its conduct that it is a vibrant regulator, receptive to the industry needs and at the same time upholding the safety interest of the worker, the public and the environment.

It is a very tight rope which AERB has to tread maintaining a fine balance. This could only be achieved through self-realization and self-awareness, where the internal conscience would hold the key for one's accountability and responsibility. No amount of external coaxing or tutoring can inculcate this sense of belongingness.

As per my understanding, all our activities should be governed by www.h (i.e. Why, what, when and how of everything). With all the staff involved, discussing "Why" while setting the goals, brings clear understanding of `why' thereby breeding `ownership' (i.e. responsibility with accountability) naturally. And this ownership, inspires and motivates staff to look for means to translate `why' into reality through `what to do', `when to do' and `how to do'.

Barring decisions concerning fundamental principles, all other decisions are contextual. Decisions of past may look inappropriate or even `absurd' in today's context but when seen in the context prevailing that time, we discover that those were the best.

Point is, what gave us success in the past may not get us more success in present situations. Introspection, retrospection is a must to revalidate our

past ways and identify need for changes. Structured ways of evolution phase may not be appropriate for accelerated growth phase.

With this background, we commenced 'manthan sessions' for introspection and retrospection in an inclusive and participative manner. The idea was that each one of us collectively form and own the decisions, which then becomes the true hallmark of a leading organization. It is a vision I have been nurturing and I am more than convinced that with the kind of overwhelming support and conviction bestowed, we shall be the trendsetter for highest standards in safety regulation.

Instead of dwelling on the major outcomes of the `manthan', which I have been sharing with you time and again through emails and notings, I would like to emphasize on some of the key aspects, which will help AERB emerge as a role model.

AERB should be respected for its knowledge and competent workforce rather than being feared for its regulatory powers. We should strive to influence the regulated facilities by sensitizing them that the regulatory actions are intended for their betterment and safety aids productivity. The challenge is that benefits of such actions are certain but not immediate or visible. Hence, it is my personal opinion that if graded approach is judiciously applied to the regulatory actions, it will go a long way in positively influencing the licensees. The utility will see regulator as part of the ecosystem and not as an alienated entity. This will eventually help to nurture a mindset from compliance oriented to continual improvement besides winning the confidence and trust of the licensee and the public.

The next point I would like to stress upon is that regulations should be as far as possible pragmatic and aligned to the specifics of a profession or trade. Else, such regulation would only remain on paper and would not be respected. The regulations should be flexible and resilient to accommodate the variance/exceptions. In this regard, for the first time series of dedicated

programmes were held to take on board the stakeholder views for practice specific guides being developed for radiation applications field. The recently issued IMS documents on Strategies and strategic Directions for Development and Revision of Regulations and Guidance and Process for Development and Revision of Regulations and Guidance, embody these sentiments. I exhort to all of you to meticulously go through these documents and understand "why" behind each statement for effective implementation.

AERB also should not shy away from taking proactive steps. Being aware of the initiative of Government to rope in public and private sector, AERB not only needs to be future ready to regulate them, but also should be able to communicate clearly its expectations to the new entrants (including the supply chain entities) so that at later stage there are no major surprises or deadlocks. One of the important aspect in this regard is the importance of safety culture in nuclear industry. AERB would be shortly engaging with such industries by holding a dedicated colloquium for the potential new entrants.

AERB is a young organization with average age of its workforce below forty. The young generation are extremely tech savvy and more conversant with the social media tools and syntax. We should be working on how to leverage the untapped talents of younger lots. I strongly advocate that we should break away from the typical bureaucratic norms and provide more avenues of information sharing by the youngsters. Learning is always bi-directional and seniors in AERB should not be reluctant in learning from juniors. The maturity of seniors and the innovative ideas from the youngsters can lead to adoption of radical and futuristic approaches. In this regard, I recall that innovative inputs provided by young volunteers during `manthan' on use of AI. I feel more such programmes should be conducted in future. One of the outcome of the `manthan', to provide an on-line platform for knowledge sharing and discussing emerging issues should be implemented at the earliest.

While, my wish list may be endless, I am hopeful that each one of you will serve as ambassadors of these ideas in the coming days and carry the baton further. Apparently, these measures on its own may not seem to be making a noticeable difference, but in entirety, these will have far reaching consequences, in-line with the quote of the famous Greek philosopher Aristotle *"the whole is greater than the sum of its parts".*

Once again I wish you all a Happy Independence day.

`Jai Hind'